सेबी

मासिक बुलेटिन

नवम्बर 2025

2025-26

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

संपादकीय समिति

- **श्री प्रभास रथ**
- **श्री साहिल मलिक**
- **सुश्री दीप्ति एल. एस.**
- **श्री जितेन्द्र कुमार**
- **डॉ. दीपाली दीक्षित**
- **श्री लालटू पोरे**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मासिक बुलेटिन का प्रकाशन सेबी के आर्थिक एवं नीति विश्लेषण विभाग द्वारा संपादकीय समिति के निदेशानुसार किया जाता है । इस बुलेटिन में प्रकाशित किए गए लेखों या व्यक्तव्यों में दिए गए आँकड़ों की सटीकता या दी गई जानकारी की सटीकता या दी गई किसी राय के लिए लेखक ही जिम्मेदार होंगे, न कि सेबी । यदि इस बुलेटिन में प्रकाशित की गई सामग्री को कहीं और प्रकाशित किया जाता है या उसका कहीं और इस्तेमाल किया जाता है, तो सेबी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि यह उल्लेख करना होगा कि यह सामग्री सेबी बुलेटिन से ली गई है ।

सेबी बुलेटिन की सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ, वर्ड और एक्सेल फॉर्मेट में सेबी की वेबसाइट (**https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics.html**) से नि:शुल्क डाउनलोड की जा सकती है, जो इस वेबसाइट पर इन शीर्षकों के तहत दी हुई है: प्रकाशन **>** रिपोर्टें और सांख्यिकी

यदि इस बुलेटिन में प्रकाशित की गई सामग्री के संबंध में आपकी कोई टिप्पणी है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अपनी टिप्पणी इस इमेल आईडी पर भेज सकते हैं: **bulletin@sebi.gov.in**

विषय-सूची

पूँजी बाजार - एक समीक्षा 4

I. कंपनियों द्वारा जुटाया गया पैसा (संलग्नक - सारणी सं. 3 से 14) 4
II. द्वितीयक बाजार के रुख (संलग्नक - सारणी सं. 1,15 से 17, 30, 31, 37 से 39, 47, 61 से 66) 6
III. डिपॉजिटरी के यहाँ कितने डीमैट खाते खुलवाए / बंद किए गए (संलग्नक - सारणी सं. 56 से 58) 10
IV. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) (संलग्नक - सारणी सं. 49) 10
V. निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) 12
क. म्यूचुअल फंड (संलग्नक सारणी सं. 53 एवं 54) 12
ख. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (संलग्नक - सारणी सं. 55) 13

भारतीय और वैश्विक वित्तीय बाजारों की समीक्षा 15

भारतीय प्रतिभूति बाजार के संबंध में उठाए गए नीतिगत कदम 22

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़) में हुई मुख्य-मुख्य गतिविधियाँ 25

पूँजी बाजार - एक समीक्षा

I. कंपनियों द्वारा जुटाया गया पैसा *(संलग्नक - सारणी सं. 3 से 14)*

- आईपीओ ने बाजार में अक्तूबर 2025 के दौरान एक नया कीर्तिमान स्थापित किया । टाटा कैपिटल लिमिटेड और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनियों की हाई-प्रोफाइल लिस्टिंग के दम पर **इस महीने कुल ₹41,783 करोड़ की भारी-भरकम रकम जुटाई गई** जो नवम्बर 2021 के ₹36,305 करोड़ के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है ।
- इस महीने **'ऑफर फॉर सेल'** में भी काफी बढ़त देखने को मिली, जो मेनबोर्ड पर आईपीओ के जरिए जुटाए गए कुल रकम का 73 प्रतिशत रहा । इसने जुलाई 2025 के पुराने मासिक उच्चतर स्तर को भी पीछे छोड़ दिया है । वहीं, इसी दौरान एसएमई आईपीओ में ओएफएस की हिस्सेदारी महज 4 प्रतिशत की रही ।
- **पश्चिमी क्षेत्र** आईपीओ और राइट्स इश्यू लाने और इनके जरिए पैसे जुटाने के मामलें में सबसे आगे रहा । महीने के दौरान कुल 63 इश्यू लाए गए थे, जिनमें से 29 इसी क्षेत्र से थे, और इनके जरिए कुल मिलाकर ₹19,847 करोड़ रुपए जुटाए गए ।

सारणी 1: कंपनियों द्वारा जुटाया गया पैसा (₹ करोड़ में)

विवरण	2025-26 (अक्तूबर 2025 तक)	अक्तूबर 2025
I. इक्विटी निर्गम (इश्यू)	**2,53,814**	**51,336**
क. आईपीओ (i+ii)	1,12,868	41,783
i.मुख्य बोर्ड	*1,05,329*	*40,402*
ii. एसएमई प्लेटफॉर्म	*7,539*	*1,381*
ख. एफपीओ	88	0
ग. इक्विटी का राइट्स इश्यू	15,559	1,050
घ. क्यूआईपी / आईपीपी	51,206	1,100
ङ. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट	74,094	7,403
II. ऋण (डैट) निर्गम	**5,50,175**	**78,540**
क. ऋण का सार्वजनिक निर्गम (डैट पब्लिक इश्यू)	6,113	834

ख. ऋण (डैट) का प्राइवेट प्लेसमेंट	5,44,062	77,706
III. रीट / इनविट	**10,348**	**3,248**
क. रीट	5,800	0
ख. इनविट	4,548	3,248
जुटाया गया कुल पैसा (I+II+III)	**8,14,337**	**1,33,124**

स्रोत: *सेबी, बीएसई और एनएसई*

- **मेनबोर्ड पर अलग-अलग क्षेत्रों (सेक्टर) में लाए गए आईपीओ:** वित्तीय वर्ष-26 में (अक्तूबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार) मेनबोर्ड (मुख्यबोर्ड) आईपीओ के जरिए जुटाई गई कुल रकम में सिर्फ वित्तीय सेवाओं की हिस्सेदारी 36 प्रतिशत की रही । वहीं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएँ, उपभोक्ता सेवाएँ और कैपिटल गुड्स से संबंधित क्षेत्रों में लाए गए आईपीओ के जरिए ₹71,050 करोड़ जुटाए गए । यह रकम मेनबोर्ड आईपीओ के जरिए जुटाई गई कुल रकम का 67 प्रतिशत है ।

आकृति 1: वित्तीय वर्ष 2025-26 (अक्तूबर 25 तक) के दौरान प्रमुख सेक्टरों द्वारा जुटाई गई रकम (₹ करोड़ में)

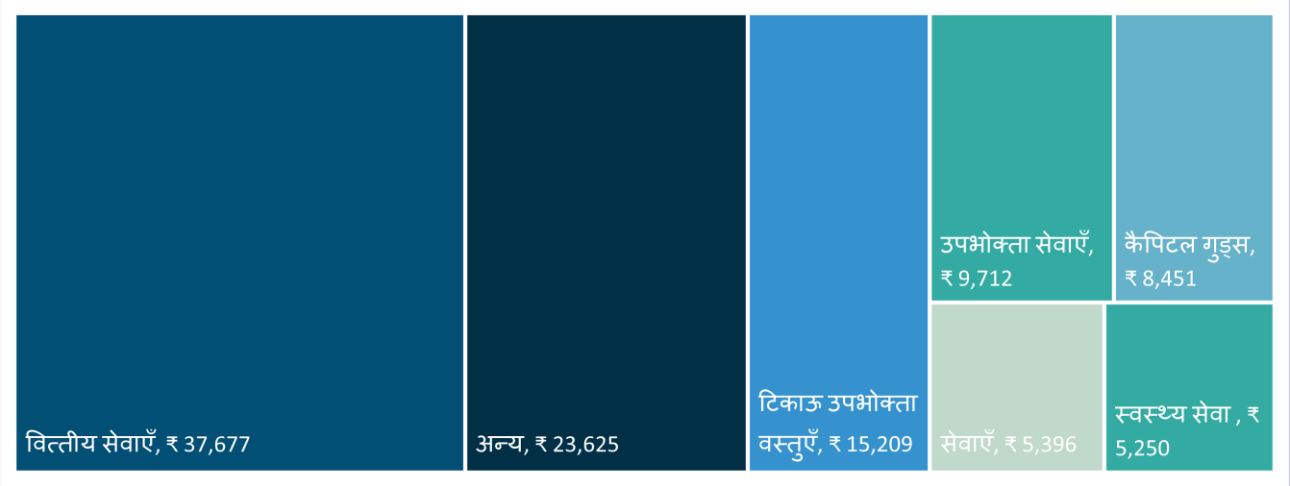

स्रोत: सेबी, बीएसई और एनएसई

- **शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण संबंधी विनियम के तहत कितने प्रस्ताव बंद किए गए:** महीने के दौरान, नियंत्रण / प्रबंधन में परिवर्तन करने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 [सेबी (सब्सटैंशियल एक्विज़ीशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) रेग्यूलेशन्स, 2011] के तहत 13 प्रस्ताव बंद हुए जिनका मूल्य ₹51 करोड़ का रहा ।

II. द्वितीयक बाजार के रुख (संलग्नक - सारणी सं. 1, 15 से 17, 30, 31, 37 से 39, 47, 61 से 66)

- **बाजार के सूचकांक:** अक्तूबर 2025 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजारों में बढ़त देखने को मिली । इस दौरान, लगभग सभी प्रमुख और अलग-अलग क्षेत्रों (सेक्टोरल) के सूचकांकों ने निवेशकों को (महीने-दर-महीने) मुनाफा दिया । बाजार के बेंचमार्क सूचकांक जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स में क्रमशः 4.5% और 4.6% की शानदार बढ़त देखने को मिली । इसके अलावा, निफ्टी मिडकैप 50 में 6.7% और स्मॉलकैप 100 में 4.7% का उछाल आया । मई 2025 के बाद यानी पिछले छह महीनों में पहली बार, भारत के सूचकांकों ने कमाई के मामले में एमएससीआई वर्ल्ड और इमर्जिंग मार्केट्स (ईएम) जैसे ग्लोबल इंडेक्स के मुक़ाबले काफी बेहतर परदर्शन किया ।

- **अलग अलग क्षेत्रों के-सूचकांक:** महीने के दौरान, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 9.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, और उसके बाद स्थान रहा निफ्टी पीएसयू बैंक (8.7%) और निफ्टी ऑयल एंड गैस (6.3%) का । पिछले तीन महीनों से भारी बिकवाली की मार झेल रहे निफ्टी आईटी ने इस महीने अच्छी वापसी की और इसमें 6.1 प्रतिशत का मुनाफा हुआ । वहीं दूसरी ओर, निफ्टी मीडिया के लिए महीना थोड़ा सुस्त रहा और इसमें 0.3 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई । इस दौरान निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिला-।

- **बाजार व्यापारावर्त (टर्नओवर)**: महीने के दौरान, इक्विटी कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग की रफ्तार कुछ धीमी रही । एनएसई के टर्नओवर में 4.1 प्रतिशत और बीएसई के टर्नओवर में 5.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई । यदि औसत दैनिक व्यापारावर्त (एडीटी) की बात करें, तो अक्तूबर 2025 के दौरान बीएसई और एनएसई दोनों का मिला-जुला एडीटी ₹1.06 लाख करोड़ रहा । यह आँकड़ा पिछले साल (अक्तूबर 2024) के मुकाबले 7 प्रतिशत कम है ।

आकृति 2: सेंसेक्स और निफ्टी 50 के व्यापारावर्त का रुख

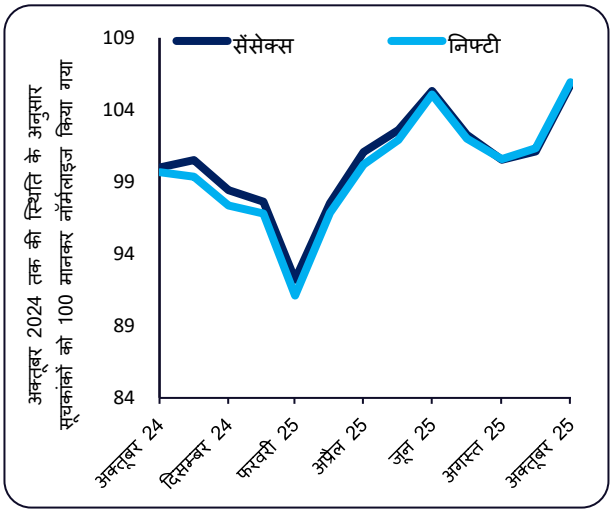

स्रोत: बीएसई और एनएसई

आकृति 3: इक्विटी कैश सेगमेंट के एडीटी का रुख (₹करोड़ में)

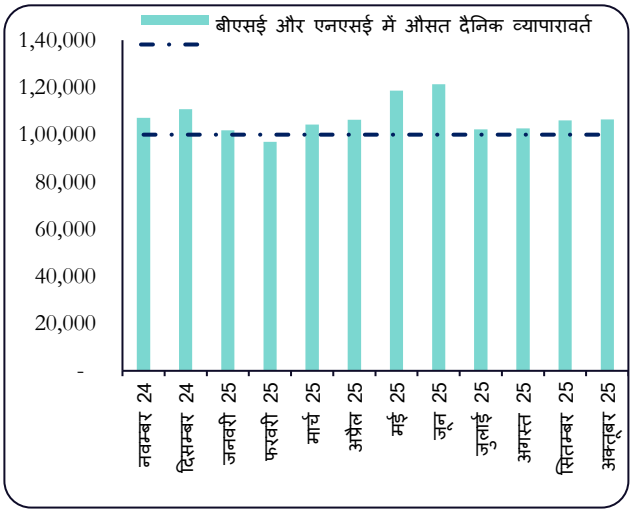

स्रोत: बीएसई और एनएसई

सारणी 2: अक्तूबर 2025 के दौरान बीएसई और एनएसई के अलग-अलग क्षेत्रों के सूचकांकों के रुख (प्रतिशत में)

अलग-अलग सेक्टरों के सूचकांक	महीने-दर-महीने नफा-नुकसान	वार्षिक उतार-चढ़ाव
निफ्टी रियल्टी	9.2	16.7
निफ्टी पीएसयू बैंक	8.7	17.4
निफ्टी ऑयल एंड गैस	6.3	11.6
निफ्टी आईटी	6.1	15.0
बीएसई एनर्जी	5.8	10.3
निफ्टी बैंक	5.7	8.4
निफ्टी मेटल	5.7	15.5
बीएसई बैंकेक्स	5.6	9.7
निफ्टी फिन सर्विसेज	4.3	9.5
बीएसई इंडस्ट्रियल्स	4.3	8.5
निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	4.0	10.7
निफ्टी हेल्थकेयर	3.9	10.6
निफ्टी फार्मा	3.4	10.0
बीएसई यूटिलिटीज	3.2	13.8
बीएसई पावर	3.1	12.9
बीएसई कैपिटल गुड्स	3.1	9.1
निफ्टी एफएमसीजी	2.7	11.5
बीएसई कमोडिटीज	2.6	10.9
बीएसई कंज्यूमर डिस्क्रीशनरी	1.9	8.3
निफ्टी ऑटो	1.0	9.3
निफ्टी मीडिया	-0.3	18.7

स्रोत: बीएसई और एनएसई

- **इक्विटी डेरिवेटिव**: अक्तूबर 2025 में इक्विटी डेरिवेटिव बाजार में अच्छी बढ़त देखने को मिली । एनएसई और बीएसई के ऑप्शन प्रीमियम के औसत दैनिक व्यापारावर्त (एडीटी) में पिछले महीने की तुलना में 19 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई । वहीं, इक्विटी फ्यूचर्स का एडीटी भी पिछले महीने की तुलना में 16 प्रतिशत चढ़कर ₹1.7 लाख करोड़ तक पहुँच गया । हालांकि, यदि पिछले साल (अक्तूबर 2024) से तुलना करें, तो सालाना आधार पर फ्यूचर्स के कारबार में 10 प्रतिशत और ऑप्शन्स प्रीमियम के कारबार में 3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई ।

आकृति 4: इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में औसत दैनिक आनुमानिक व्यापारावर्त के रुख (₹ करोड़ में)

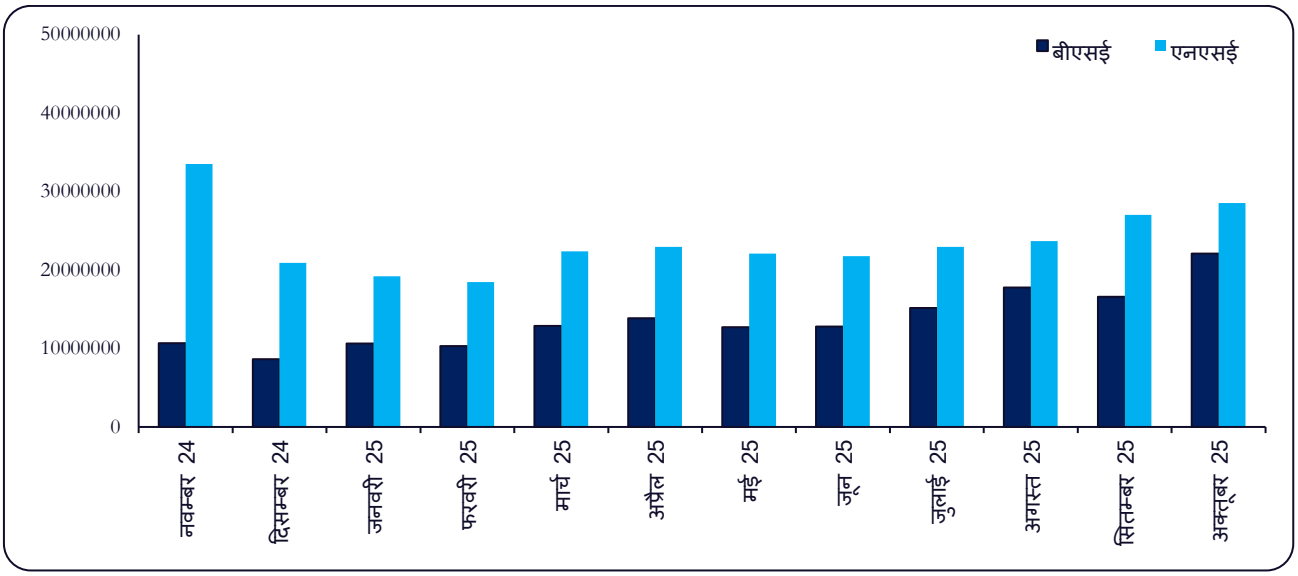

स्रोत: *बीएसई और एनएसई*

- **करेंसी डेरिवेटिव:** अक्तूबर 2025 के दौरान बीएसई और एमएसईआई के करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई कारबार नहीं हुआ, जबकि एनएसई के आनुमानिक व्यापारावर्त में पिछले महीने की तुलना में 22 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की गई ।
- **इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव:** बीएसई में इस सेगमेंट में अप्रैल 2024 से ही कोई ट्रेडिंग नहीं हुई । वहीं दूसरी ओर, एनएसई में (फरवरी-25 से जुलाई-25 तक लगातार छह महीनों की गिरावट के बाद) अगस्त 2025 से कारबार में बढ़त का रुख बना हुआ है । अक्तूबर 2025 के दौरान, पिछले महीने की तुलना में व्यापारावर्त में 11 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है ।

आकृति 5: करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में आनुमानिक व्यपारावर्त के रुख (₹ करोड़ में)

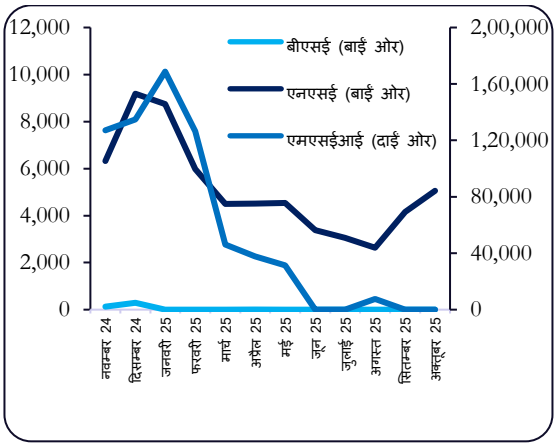

स्रोत: *बीएसई, एनएसई और एमएसईआई*

आकृति 6: इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सेगमेंट में आनुमानिक व्यपारावर्त के रुख (₹ करोड़ में)

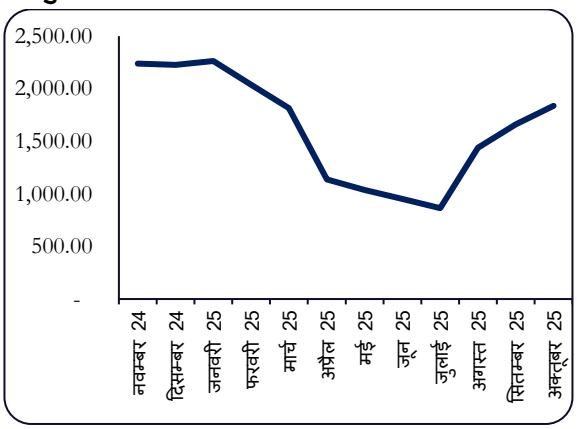

स्रोत: *बीएसई और एनएसई*

- **कमोडिटी डेरिवेटिव:** महीने के दौरान, एमसीएक्स आईकॉमडेक्स कंपोजिट इंडेक्स में 3.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जिससे अप्रैल-अक्तूबर 2025 के दौरान कुल मुनाफा 20.8 प्रतिशत पर पहुँच गया । यदि सूचकांक के अलग-अलग क्षेत्रों पर नजर डालें, तो बुलियन और धातु सूचकांक ने क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत का मुनाफा दिया । वहीं दूसरी ओर, एनर्जी इंडेक्स में सुस्ती छाई रही और अक्टूबर 2025 के दौरान इसमें 1.9 प्रतिशत की गिरावट देखने को भी मिली ।

आकृति 7: देश के कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार के सूचकांकों में हुआ उतार-चढ़ाव

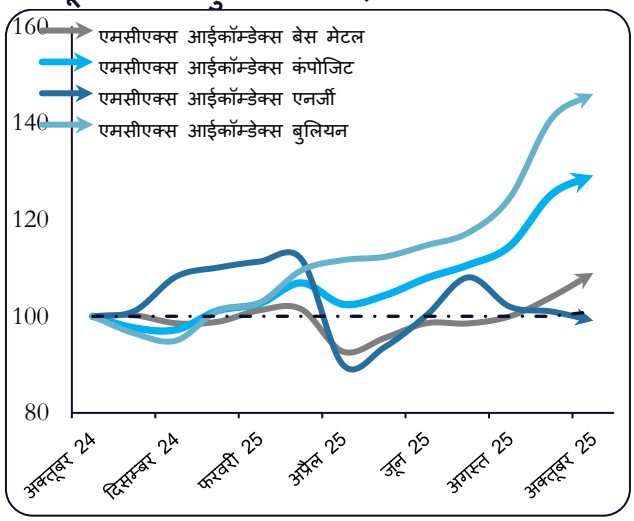

स्रोत: ***एमसीएक्स;*** सितम्बर-24 से सभी सूचकांकों को 100 पर नॉर्मलाइज किया गया है

आकृति 8: कृषि कमोडिटी डेरिवेटिव के व्यापारावर्त (टर्नओवर) के रुख

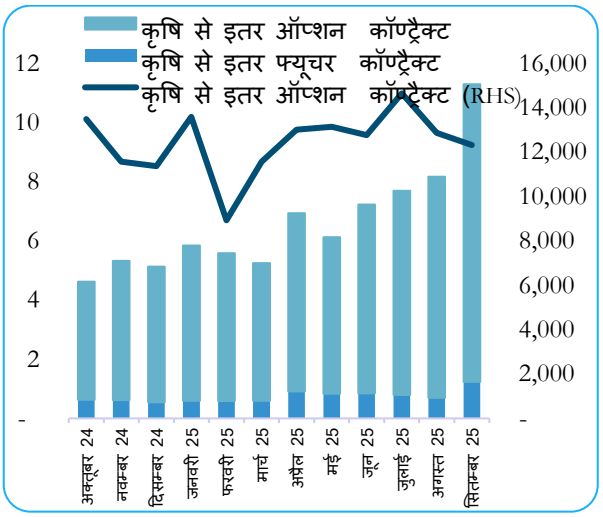

स्रोत: *एमएक्ससी और एनसीडीईएक्स*

III. डिपॉजिटरी के यहाँ कितने डीमैट खाते खुलवाए / बंद किए गए *(सारणी 56 से 58)*

- **डीमैट खातों की संख्या में वृद्धि**: अक्टूबर 2025 में, एनएसडीएल में 4.3 लाख नए डीमैट खाते खोले गए । इसका मतलब यह हुआ कि पिछले महीने के मुकाबले कुल खातों की संख्या में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । वहीं, सीडीएसएल में 25.6 लाख नए खाते खोले गए, और इस प्रकार, सितम्बर 2025 की तुलना में डीमैट खातों की संख्या में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई । अक्तूबर 2025 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, एनएसडीएल में 4.2 करोड़ डीमैट खाते थे और सीडीएसएल में 16.8 करोड़ खाते थे, और इस तरह से भारत में डीमैट खातों की कुल संख्या 21 करोड़ से भी अधिक हो गई ।

आकृति 9: खुलवाए गए नए डीमैट खाते (महीने के अनुसार) [लाख में]

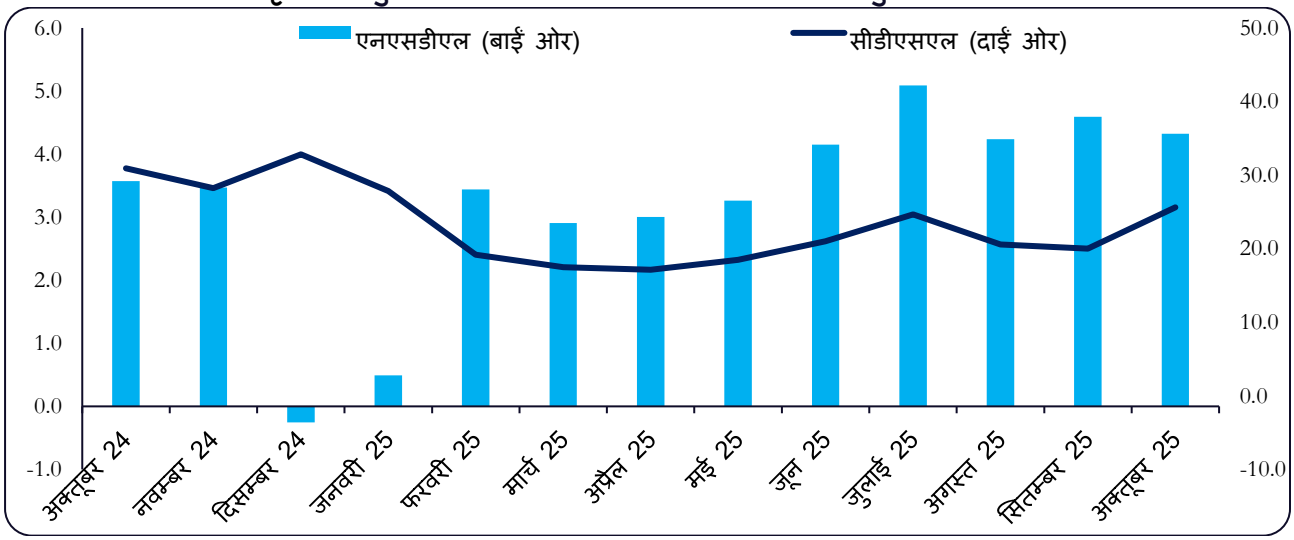

स्रोत: *सीडीएसएल और एनएसडीएल*

IV. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक[1] (एफपीआई) *(संलग्नक - सारणी सं. 49)*

- **कुल निवेश:** अक्तूबर 2025 के दौरान एफपीआई ने कुल मिलाकर खरीददारी की । यदि सितम्बर 2025 से तुलना करें तो जहाँ इस दौरान एफपीआई ने ₹12,539 करोड़ की बिकवाली की थी, वहीं

[1] एफपीआई द्वारा शुद्ध रूप से किए गए निवेश में सितम्बर 2024 से म्यूचुअल फंडों में किए गए निवेश शामिल हैं ।

अक्तूबर 2025 के दौरान उन्होंने ₹35,598 करोड़ का शुद्ध निवेश किया । इसमें इक्विटी सेगमेंट में ₹14,610 करोड़ और डैट सेगमेंट में ₹18,224 करोड़ का निवेश किया गया ।

- **इक्विटी सेगमेंट** में, एफपीआई ने द्वितीयक बाजार में ₹3,902 करोड़ का निवेश किया और प्राथमिक बाजार के जरिए ₹10,708 करोड़ का निवेश किया । अक्तूबर के शुरूआती 15 दिनों के मुकाबले अंतिम 15 दिनों के दौरान विदेशी निवेशकों ने काफी ज्यादा पैसे निवेश किए । भारतीय कंपनियों के दमदार मुनाफे और बाजार में गिरावट के बाद शेयरों के दाम वाजिब होने की वजह से निवेशकों का भरोसा लौटा है । साथ ही, दुनियाभर के बड़े निवेशक अब सिर्फ एआई और टेक्नोलॉजी जैसे चुनिंदा सेक्टरों में पैसा लगाने के बजाय भारतीय बाजार जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं । इसके अलावा, अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद और भारत-अमेरिकी व्यापार वार्ता को लेकर मचे उत्साह ने भी निवेशकों का हौसला बढ़ाया है ।

- ऋण (डैट) सेगमेंट में, फुल्ली एक्सेसेबल रुट (एफएआर) और ऋण सामान्य सीमा के जरिए क्रमशः ₹15,144 करोड़ और ₹3,507 करोड़ निवेश किए गए जबकि वीआरआर के जरिए ₹427 करोड़ निकाल लिए गए ।

आकृति 10: एफपीआई निवेश के रुख (₹ करोड़ में)

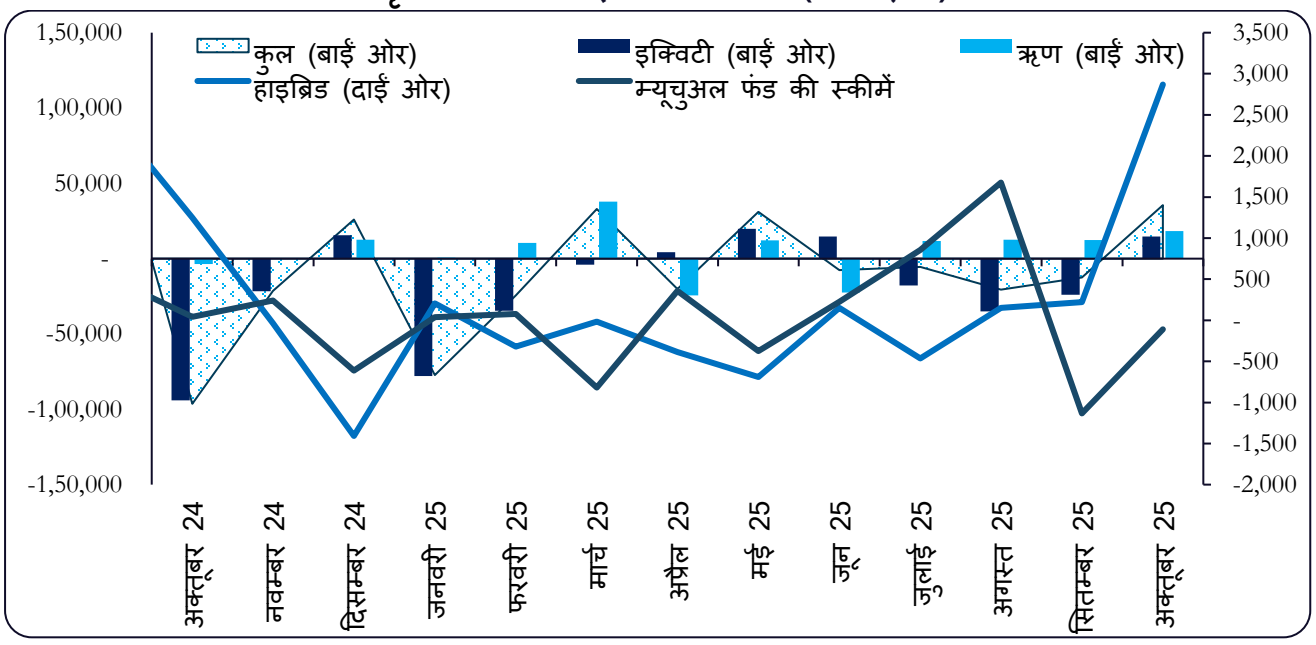

स्रोत: एनएसडीएल

V. निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट)

क. म्यूचुअल फंड *(संलग्नक सारणी सं. 53 एवं 54)*

- अक्तूबर 2025 के अंत तक की स्थिति के अनुसार म्यूचुअल फंड की कुल **प्रबंधनाधीन आस्तियाँ** (माह-दर-माह) 5.6 प्रतिशत बढ़कर ₹79.9 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई । यह उछाल निवेशकों के बढ़ते भरोसे और बाजार में अधिक पैसे लगाए जाने की वजह से देखने को मिला है । यदि पूरे वित्तीय वर्ष 26 (अक्तूबर तक) की बात करें, तो म्यूचुअल फंडों ने कुल ₹89.2 लाख करोड़ जुटाए, जबकि इस दौरान निवेशकों ने ₹81.6 लाख करोड़ निकाल लिए । इस तरह से बाजार में कुल मिलाकर ₹7.6 लाख करोड़ का निवेश किया गया ।

आकृति 11: अलग-अलग स्कीमों के अनुसार म्यूचुअल फंडों की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (₹ लाख करोड़ में)

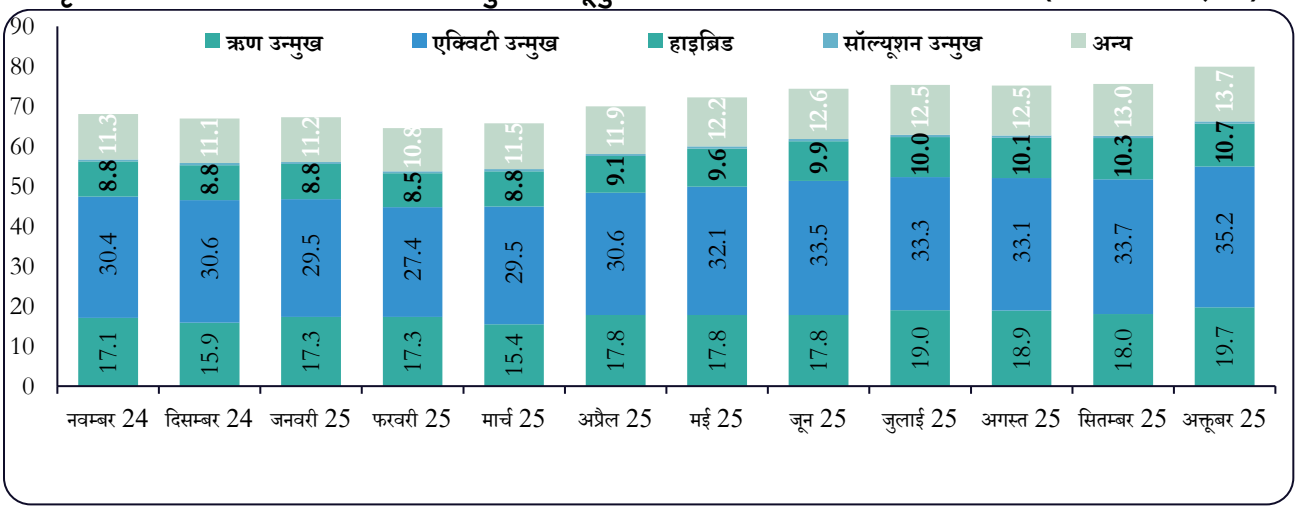

स्रोत: सेबी

- अक्तूबर 2025 के अंत की स्थिति के अनुसार, म्यूचुअल फंडों की कुल स्कीमों की संख्या बढ़कर 1,865 हो गई, जो पिछले महीने 1,849 थी । इसी के साथ सितम्बर 2025 के अंत तक की स्थिती के अनुसार फोलियो की कुल संख्या 25.2 करोड़ थी, जो अक्तूबर 2025 के अंत तक बढ़कर 25.6 करोड़ पर पहुँच गई ।

- अक्तूबर-25 के दौरान, इनकम / डैट ओरिएंटेड स्कीमों के जरिए ₹1,59,899 करोड़ निवेश किया गया । इसकी मुख्य वजह संस्थागत निवेशकों द्वारा बाजार में दोबारा निवेश किया जाना रही, जिन्होंने

सितम्बर में अग्रिम कर के भुगतान और तिमाही बैलेंस शीट संबंधी जरूरतों के मद्देनज़र बड़ी रकम निकाल ली थी । उसी तरह से ग्रोथ/इक्विटी ओरिएंटेड स्कीमों के जरिए रिकॉर्ड ₹24,672 करोड़ जुटाए गए । इसके बाद अन्य स्कीमों (इंडेक्स फंड, ईटीएफ और एफओएफ) का स्थान रहा, जिनके जरिए कुल मिलाकर ₹16,668 करोड़ जुटाए गए और हाइब्रिड स्कीमों के जरिए ₹14,156 करोड़ और सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीमों के जरिए ₹261 करोड़ जुटाए गए ।

- अक्तूबर 2025 के दौरान, म्यूचुअल फंडों ने इक्विटी में कुल मिलाकर ₹23,609 करोड़ का निवेश किया । इसके विपरीत, म्यूचुअल फंडों ने लगातार 18वें महीने भी ऋण प्रतिभूतियों की बिकवाली की और इस महीने उन्होंने कुल मिलाकर ₹6,393 करोड़ की बिकवाली की ।

आकृति 12: द्वितीयक बाजार में म्यूचुअल फंडों द्वारा कुल-मिलाकर की गई खरीद/ बिक्री के रूख (₹ करोड़ में)

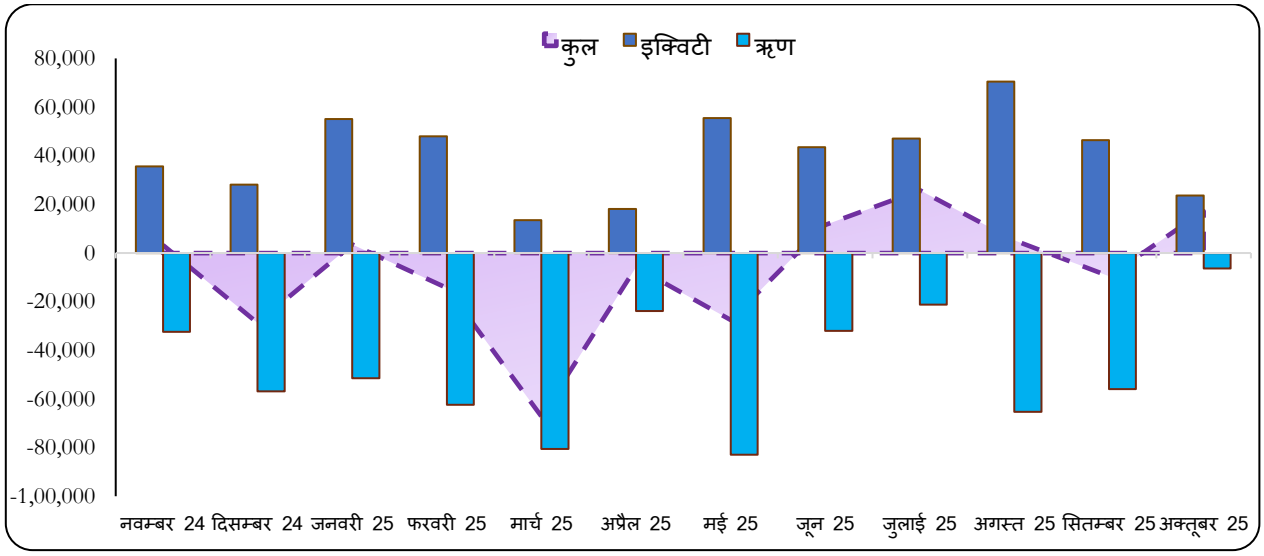

स्रोत: सेबी

ख. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (संलग्नक सारणी सं. - 55)

- सितम्बर 2025 में, पोर्टफोलियो प्रबंधन उद्योग की कुल प्रबंधनाधीन आस्तियाँ ₹40.3 लाख करोड़ की रही ।

आकृति 13: पोर्टफोलियो प्रबंधकों के ग्राहकों की संख्या और उनकी प्रबंधनाधीन आस्तियाँ

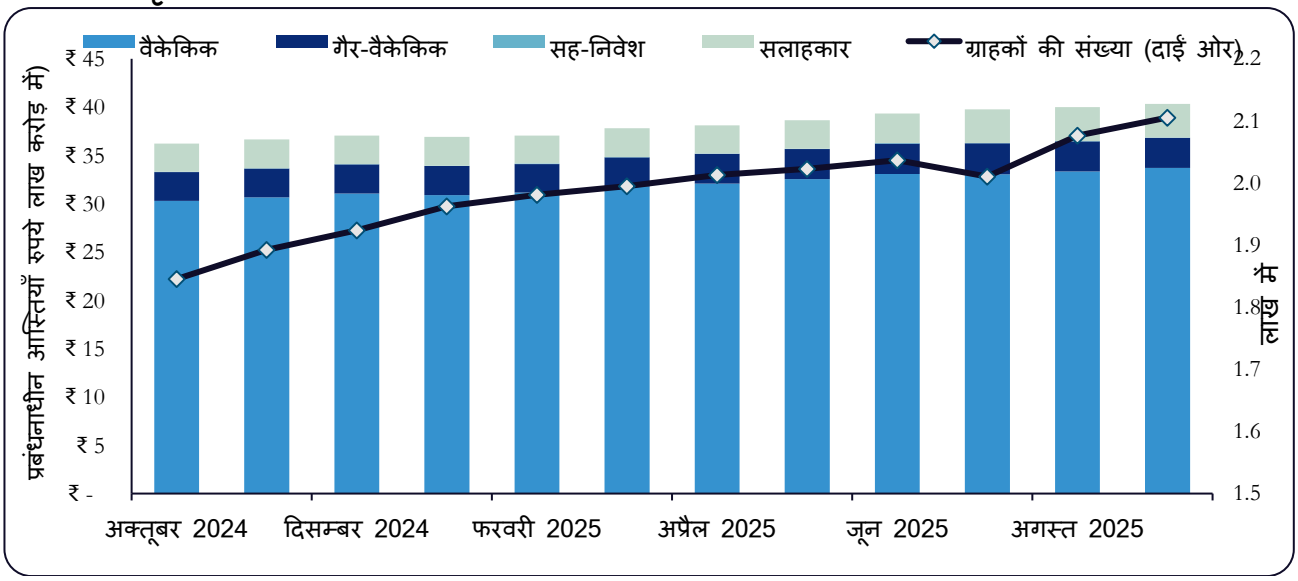

भारतीय और वैश्विक बाजारों की समीक्षा

- **वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में भारत की चौंका देने वाली जीडीपी ग्रोथ:** भारत की जीडीपी पिछले छह तिमाहियों के उच्चतम स्तर पर पहुँचकर 8.2 प्रतिशत (साल-दर-साल) हो गई । इन आँकड़ों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है और भारतीय बाजारों की घरेलू मांग अब भी कितनी मजबूत है ।
- **वैश्विक संस्थाओं ने भी जताया भारत के मजबूत अर्थव्यवस्था पर भरोसा:** दुनियाभर में चल रही भू-राजनीतिक उथल-पुथल और डगमगाते आर्थिक हालातों के बीच, तमाम वैश्विक एजेंसियाँ भारत को सबसे दमदार प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में देख रही हैं । अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपनी अक्तूबर 2025 की 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक' रिपोर्ट में साल 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है । यह पिछले जुलाई के अनुमान से 0.20% (20 बेसिस पॉइंट) ज्यादा है । आईएमएफ का मानना है कि साल की पहली तिमाही में भारत का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर रहा है, जिसने वैश्विक स्तर पर हो रहे उतार-चढ़ाव और बाहरी दबावों को बखूबी मात दी है ।

सारणी 3: जीडीपी विकास दर: आईएमएफ के ताजा अनुमान

क्षेत्र	2025	2026	क्षेत्र	2025	2026
दुनियाभर में हुआ कुल उत्पादन	3.2	3.1	उभरते बाजार और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं	4.1	3.9
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.6	1.6	उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	4.2	4.0
अमेरिका (यूएस)	2.0	2.1	भारत	**6.6**	**6.2**
यूके	1.3	1.3	चीन	4.8	4.2
यूरो क्षेत्र	1.2	1.1	सऊदी अरब	4.0	4.0
जर्मनी	0.2	0.9	नाइजीरिया	3.9	4.2
फ्रांस	0.7	0.9	ब्राजील	2.4	1.9
कनाडा	1.2	1.5	रूस	0.6	1.0
अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं	1.8	2.0	कम आय वाले विकासशील देश	4.4	5.0

स्रोत: *आईएमएफ*

- **दुनियाभर में आईपीओ की क्या स्थिति रही:** महीने के दौरान, दुनियाभर की 139 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए कुल 22 अरब डॉलर (22 बिलियन डॉलर) की भारी-भरकम रकम जुटाई । ब्रिटेन में रजिस्टर वेरीश्योर का आईपीओ महीने का सबसे बड़ा आकर्षण रहा । इस कंपनी ने 4.2 अरब डॉलर (4.2 बिलियन डॉलर) से भी अधिक रकम जुटाई, जो 2022 के बाद यूरोप का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हुआ । वैश्विक स्तर पर वेरीश्योर के बाद भारत की टाटा कैपिटल का नाम रहा । घरेलू बाजारों में

लिस्ट हुई इस कंपनी ने 1.7 अरब डॉलर (1.7 बिलियन डॉलर) जुटाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई । दुनियाभर के शीर्ष पाँच आईपीओ ने मिलकर 10 अरब डॉलर (10 बिलियन डॉलर) से भी अधिक रकम जुटाई, जिसमें खास बात यह रही कि इन पाँच आईपीओ में से दो आईपीओ भारत से थे।

- दुनियाभर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितताओं और बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत के प्राथमिक बाजार में सबसे ज्यादा आईपीओ लाए गए । इसके बाद चीन और जापान का स्थान रहा । आईपीओ की वैल्यू (मूल्य) और वॉल्यूम (संख्या) दोनों ही मामलों में एशियाई देशों ने दुनियाभर में अपनी बादशाहत कायम रखी है । अक्तूबर 2025 के दौरान रकम जुटाए जाने के मामले में यूरोप ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है।

आकृति 14: आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम (मिलियन $ में)

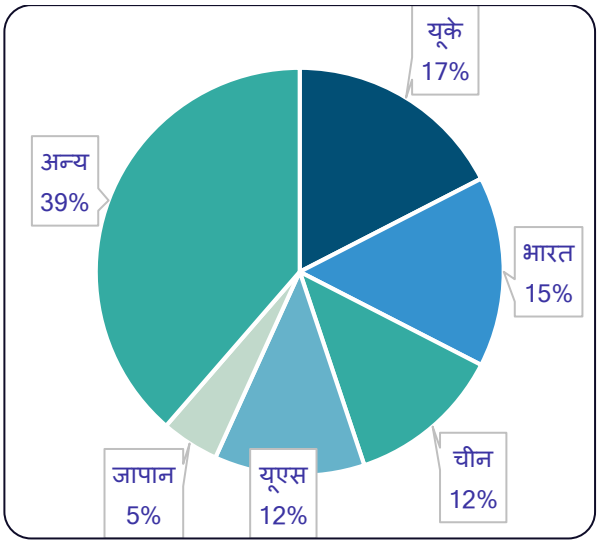

आकृति 15: दुनियाभर में कितने आईपीओ लाए गए

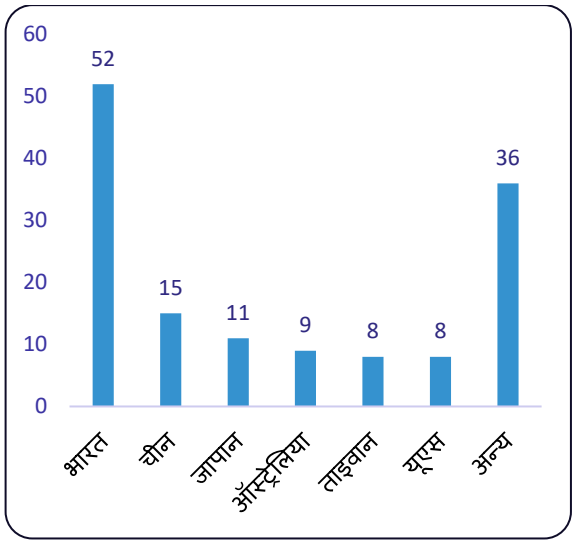

स्रोत: ब्लूमबर्ग

- अक्तूबर 2025 के दौरान दुनियाभर में आईपीओ के जरिए रकम जुटाए जाने के मामले में **'कमर्शियल सर्विसेज'** सेक्टर सबसे आगे रहा । इसके बाद **'डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज', 'मशीनरी - कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग'** और **'रिटेल'** सेक्टर का स्थान रहा । इन चारों सेक्टरों ने मिलकर इस महीने वैश्विक स्तर पर आईपीओ से जुटाई गई कुल रकम का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा अपने नाम किया ।

आकृति 16: दुनियाभर का आईपीओ बाजार: किस सेक्टर ने कितना रकम जुटाया

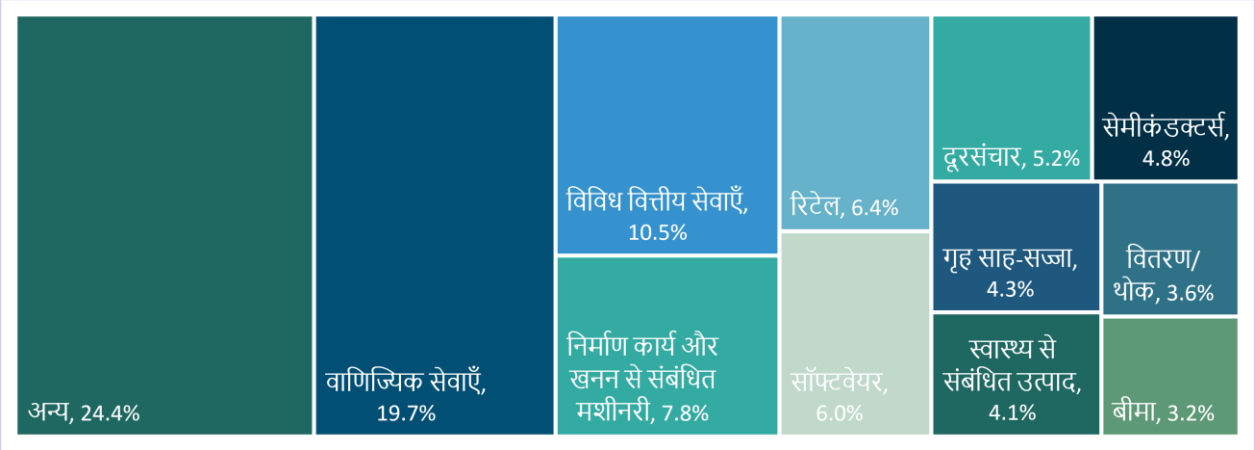

स्रोत: ब्लूमबर्ग उद्योगों और सेक्टर का बंटवारा ब्लूमबर्ग के मानकों के आधार पर किया गया है ।

- **दुनियाभर के इक्विटी सूचकांक:** अक्तूबर 2025 के दौरान डॉलर के मुकाबले वैश्विक बाजारों ने भारतीय सूचकांकों की तुलना में कहीं बेहतर प्रदर्शन किया । इस बढ़त की मुख्य वजह सेमीकंडक्टर, कैपिटल इक्विपमेंट और एआई से जुड़े हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर सेक्टर में आई जबरदस्त उछाल रही । महीने के दौरान, दुनियाभर के बाजारों में दक्षिण कोरिया 17.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद जापान (11.8 प्रतिशत) और ताइवान (8.4 प्रतिशत) का स्थान रहा । अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के कम होने और कंपनियों के अच्छे नतीजों के दम पर अमेरिकी सूचकांक एस एंड पी 500 और नैस्डैक ने नए रिकॉर्ड स्तर को छू लिया । यूरोप की बात करें तो गिल्ट बॉण्डों से मिलने वाले लाभ में कमी आने से ब्रिटेन का एफटीएसई 100 सूचकांक 1.4 प्रतिशत चढ़ा और अपने पड़ोसी देशों से आगे निकल गया । एआई सेक्टर से ज्यादा जुड़ाव न होने के कारण फ्रांस के बाजार में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) की कमी होने की वजह से जर्मनी का बाजार (डीएएक्स) गिरकर बंद हुआ ।

- उन देशों के बाजारों में सुस्ती देखी गई जिनका अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ता ज्यादा है या जिन पर अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर पड़ता है; भारत भी इन्हीं देशों की फेहरिस्त में शामिल रहा । हालांकि, यदि हम उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, तो भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा और भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने डॉलर के आधार पर 4.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की ।

आकृति 17: बड़े अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में हुआ नफा-नुकसान (अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में)

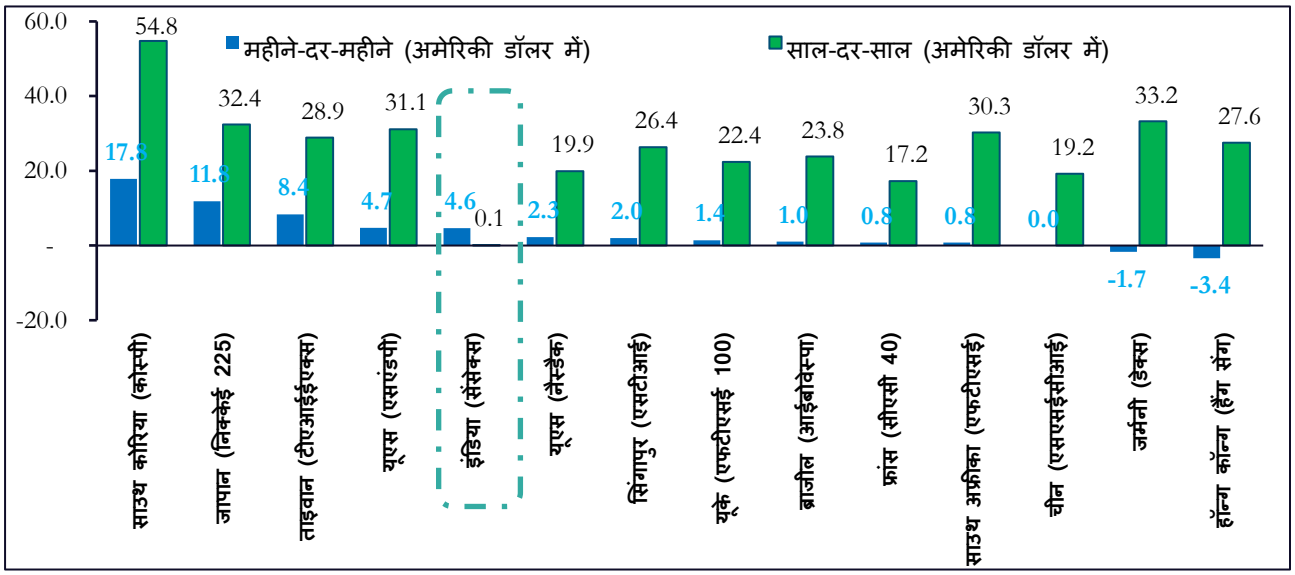

स्रोत: ब्लूमबर्ग

- दुनियाभर के प्रमुख बाजारों में पिछले बारह महीनों का पी/ई रेशो ऊंचे स्तर पर बना हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि निवेशक अभी बाजार को लेकर तो सावधान हैं, लेकिन उसके साथ-साथ सकारात्मक उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं । भारतीय शेयर बाजार अभी भी दुनिया के सबसे महंगे बाजारों में से एक बना हुआ है और यह अमेरिका के बाजारों से केवल थोड़ा ही पीछे है । अक्तूबर 2025 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, निफ्टी-50 का पी/ई रेशो 22.7 दर्ज किया गया, जो इस बात का सबूत है कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारतीय बाजार पर निवेशकों को अटूट भरोसा है ।

आकृति 18: कुछ चुनिंदा देशों का पिछले एक साल का प्राइस अर्निंग रेशो

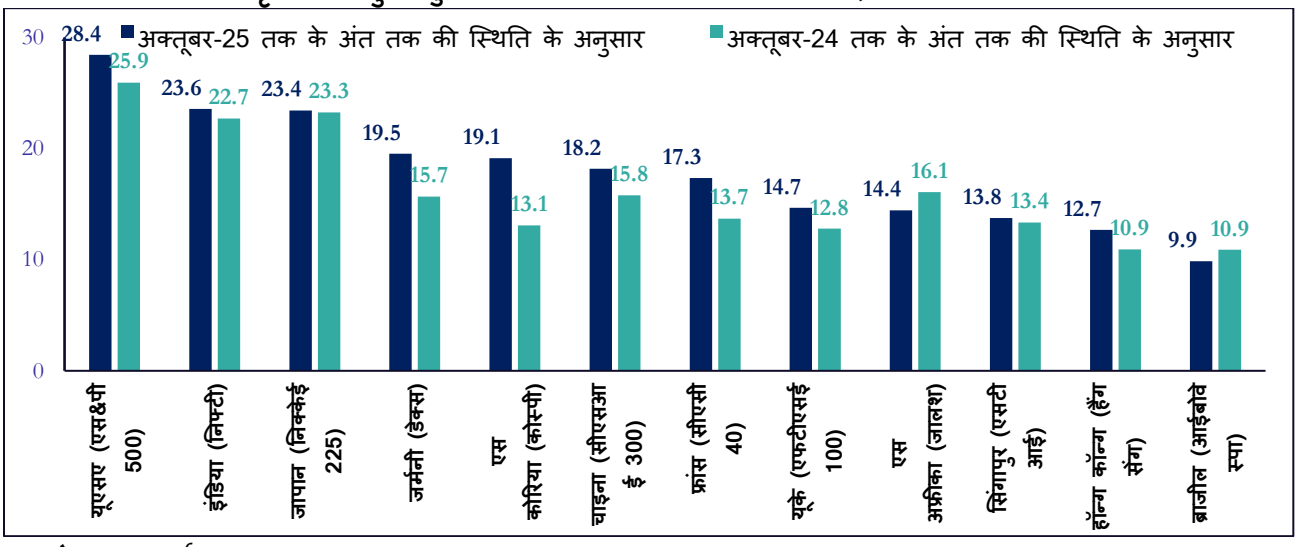

स्रोत: *ब्लूमबर्ग*

- अक्तूबर 2025 के अंत तक की स्थिति के अनुसार भारत के 10 वर्षीय सरकारी बॉण्डों से पिछले महीने की तुलना में कम लाभ मिला । महीने के दौरान, अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया थोड़ा कमजोर हुआ, जिसकी मुख्य वजह डॉलर इंडेक्स में आई मजबूती और उभरते बाजारों द्वारा पैसा निकालना रही । हालांकि, राहत की बात यह है कि दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में रुपये की यह गिरावट काफी कम रही । यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि तमाम वैश्विक दबावों के बावजूद भारत की स्थिति काफी मजबूत है ।

सारणी 4: 10-वर्ष वाले सरकारी बॉण्ड पर मिलने वाला प्रतिफल (प्रतिशत में)

देश	31-अक्तूबर-25 तक की स्थिति के अनुसार	30-सितम्बर-25 तक की स्थिति के अनुसार	31-अक्तूबर-24 तक की स्थिति के अनुसार
अमेरिका	4.1	4.2	4.3
यूके	4.4	4.7	4.4
फ्रांस	3.4	3.5	3.1
जर्मनी	2.6	2.7	2.4
जापान	1.7	1.6	0.9
चीन	1.8	1.9	2.1
दक्षिण कोरिया	3.1	3.0	3.1
भारत	6.5	6.6	6.8
सिंगापुर	1.9	1.9	2.8
ब्राजील	13.8	13.7	12.8
मेक्सिको	8.8	8.8	10.1

सारणी 5: विकसित और विकासशील बाजार के मुख्य मुद्राओं (करेंसी) के एक्सचेंज दर में हुआ उतार-चढ़ाव

मुद्रा	31-अक्तूबर-2025 को एक्सचेंज रेट	1-महीने में	1-वर्ष	साल-दर-साल
		(प्रतिशत में)		
यूरो	0.8668	1.7	-6.2	-5.7
पाउंड	0.7603	2.2	-1.8	-1.9
रूबल	0.0124	2.5	2.8	20.4
रियाल	5.3766	1.0	-5.8	-7.1
रैंड	17.3325	0.4	-5.4	-1.5
येन	153.99	4.1	2.7	1.3
वोन	1430	1.9	-2.9	3.9
रेनमिन्बी	7.1194	0.0	-1.9	0.0
रुपया	88.7725	0.0	3.9	5.6

टिप्पणी:

1. सभी मुद्रा दरें यूएसडी की तुलना में दी गई हैं ।

2. ऋणात्मक चिन्ह (जो प्रतिशत बदलाव के आँकड़ों में दर्शाया गया है) यह दर्शाता है कि उस मुद्रा में अमरीकी डॉलर (बेस करेंसी) की तुलना में मजबूती आई है ।

बदलते भारत की नई आर्थिक पहचान: वर्ल्ड बैंक ने माना भारत की अर्थव्यवस्था का लोहा

फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम (एफएसएपी) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वर्ल्ड बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त अभियान है, जिसके तहत किसी भी देश के वित्तीय ढांचे का बेहद बारीकी और गहराई से विश्लेषण किया जाता है । साल 2024 के दौरान किए गए व्यापक मूल्यांकन के आधार पर, **विश्व बैंक ने 30 अक्टूबर 2025 को 'इंडिया - फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट' (एफएसए) रिपोर्ट जारी की है ।**

विश्व बैंक की रिपोर्ट की एक झलक:

- साल 2017 के बाद से भारत का वित्तीय ढाँचा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समावेशी हुआ है । आर्थिक सुधारों की बदौलत ही भारत 2010 के दशक के मुश्किल दौर और कोरोना महामारी के झटकों से सफलतापूर्वक उबरने में कामयाब रहा है । हालांकि, 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के लिए इन सुधारों को और रफ्तार देनी होगी ।
- **बैंकिंग और एनबीएफसी संबंधी विनियम और निगरानी:** वर्ल्ड बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी की निगरानी के संबंध में आरबीआई की भूमिका की सराहना की है । सरकारी नियमों और सूझबूझ से कर्ज देने का ढांचा मजबूत हुआ है । लेकिन अभी एमएसएमई सेक्टर को बेहतर कर्ज की सुविधाएं देने और जोखिम प्रबंधन को और पुख्ता करने की जरूरत है ।

- **भारतीय पूंजी बाजार:** कड़े नियमों और सुधारों के चलते भारत का पूँजी बाजार 2017 में जीडीपी के 144% से बढ़कर 2024 में 175% हो गया है । अलग-अलग तरह के निवेशकों के जुड़ने से बाजार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है । रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि जोखिमों पर नजर रखने के लिए एक साथ मिलकर काम करने वाला तरीका अपनाया जाए और निगरानी करने वाली संस्थाओं के नियमों को और भी कड़ा किया जाए ।

- **वित्तीय समावेशन:** विश्व बैंक ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बताया है । रिपोर्ट में आम जनता तक वित्तीय सेवाएं पहुँचाने वाली सरकारी योजनाओं की जमकर तारीफ की गई है । हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ाने की जरूरत है । साथ ही, आम लोगों और एमएसएमई की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बाजार में और भी नए तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाने का सुझाव दिया गया है ।

- **भारत का बीमा क्षेत्र:** भारत का बीमा क्षेत्र अपने साथी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से विकसित हो रहा है, जो वैश्विक मानकों और बेहतरीन कार्यप्रणालियों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को

दर्शाता है । वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लाइसेंस संबंधी प्रक्रियाओं, नियमों को लागू करने की शक्ति और जनता को जानकारी देने की बेहतर व्यवस्था के कारण बीमा क्षेत्र लगातार विकास हो रहा है ।

- **जलवायु संबंधी जोखिमों का विश्लेषण:** वर्ल्ड बैंक के विश्लेषण के अनुसार, भारत का कृषि और बैंकिंग क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के छोटे झटकों को झेलने के लिए फिलहाल तैयार और मजबूत है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरती गई तो यह भविष्य में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकता है । रिपोर्ट में पर्यावरण के अनुकूल निवेश को तेजी से बढ़ाने की सिफारिश की गई है । साथ ही, बेहतर वित्तीय व्यवस्था के लिए एक 'सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप' तैयार करने और जलवायु के क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश संबंधी नियमों के संबंध में 'नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी' बनाने का सुझाव दिया गया है ।

भारतीय प्रतिभूति बाजार के संबंध में उठाए गए नीतिगत कदम

In October 2025, SEBI introduced a series of policy measures aimed at strengthening investor protection, enhancing market transparency and improving overall operational efficiency across registered market intermediaries.

The brief on these policy initiatives/press releases are outlined below:

1. **SEBI rolls out "Validated UPI Handles" and "SEBI Check" for secure investor payments**

   Further to its press release dated June 11 2025, the initiatives on Validated UPI Handles and SEBI Check are live and available for investors. The UPI IDs of SEBI-registered investor-facing intermediaries will now carry the exclusive "@valid" handle, issued by NPCI, along with category-specific suffixes that will enable investors to easily identify legitimate entities. To further empower investors, SEBI Check functionality has been developed which, irrespective of any payments mode, will help investors to verify and confirm the authenticity of the bank account details of SEBI registered intermediaries. These two rollouts are expected to significantly enhance investor protection by curbing fraudulent money collections by unregistered entities.

   PR No.: 64/2025 dated Oct 1, 2025

2. **Review of Block Deal Framework**

   SEBI, vide circular dated December 10, 2024 prescribed framework for block deal window under the optional T+0 settlement cycle in addition to the block deal windows under the T+1 settlement cycle. Based on the recommendations of the Working Group, deliberations in Secondary Market Advisory Committee (SMAC) of SEBI and public comments received, certain provisions like operating hours, price range, order size etc. of block deal window have been modified. The above provisions will be applicable for the block deal window under both T+1 settlement cycle and optional T+0 settlement cycler

   SEBI/HO/MRD/POD-III/CIR/P/2025/134 dated Oct 08, 2025

3. **Rationalization and standardization of penalties levied on stock brokers by stock exchanges**

   SEBI rationalized and standardised penalty framework for levying penalties on stock brokers by stock exchanges. As per existing framework, penalties for similar observations differ across exchanges, and at times, brokers having membership with multiple exchanges may face multiple penalties for the

same observation. As per recommendations of the Working Group constituted by SEBI, and subsequent deliberations, a revised penalty framework was issued by the stock exchanges. It aims to standardise and bring in uniformity and adopt the terminology 'financial disincentive' in place of 'penalty' for procedural lapses/technical errors.

PR No.:66/2025 dated Oct 10, 2025

4. **Minimum information to be provided to the Audit Committee and Shareholders for approval of Related Party Transactions**

SEBI through various circulars had mandated listed entities to follow "Minimum information to be provided to the Audit Committee and Shareholders for approval of Related Party Transactions" (RPT Industry Standards), formulated by Industry Standards Forum (ISF). Based on the request, received from ISF, on relaxation from applicability of the RPT Industry Standards and subsequent discussions with Advisory Committee on Listing Obligations and Disclosures (ACLOD) of SEBI, the SEBI Board approved the relaxation in minimum information to be provided to the Audit Committee and shareholders for the approval of RPTs.

SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2025/135 dated Oct 13, 2025

5. **Transfer of portfolios of clients (PMS business) by Portfolio Managers**

For the purpose of simplification and ease of doing business, SEBI has allowed the transfer of PMS business from one portfolio manager to another, subject to prior approval. The PMS business can be transferred from one Portfolio Manager to another in the same group and even not belonging to the same group.

SEBI/HO/IMD/RAC/CIR/P/2025/ 138 dated Oct 24, 2025

6. **Enabling Investment Advisers (IAs) to provide second opinion to clients on assets under pre-existing distribution arrangement**

As per the extant guidelines w.r.t Investment Advisers it is specified that any portion of Assets Under Advice (AUA) held by the client under any pre-existing distribution arrangement with any entity shall be deducted from AUA for the purpose of charging fee by the IA and hence IAs are not allowed to charge AUA based fee on such assets. However, based on the representation from Industry association of IAs and in order to provide investors the opportunity of obtaining a second opinion on assets under pre-existing distribution arrangement with other entity, IAs are now permitted to charge AUA based fee in such scenarios and provide second opinion to their clients.

HO/38/12/11(1)2025-MIRSD-POD/ I/71/2025 dated Oct 30, 2025

7. **Interim arrangement for certified past performance of Investment Advisers and Research Analysts prior to operationalization of Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA)**

In order to display the performance of Investment Advisers (IAs) and Research Analysts(RAs), SEBI specified the framework for creation and operationalization of PaRRVA, which will carry out the verification activities of IAs/RAs prospectively for the period post on-boarding. However, considering representation of the industry, SEBI has allowed IAs/RAs to provide past performance data, certified by a member of ICAI/ICMAI, only upon specific request of the client (including prospective client).

HO/38/12/11(1)2025-MIRSD-POD/ I/73/2025 dated Oct 30, 2025

(Note: Circulars related to extension of timelines or those of procedural nature have not been included.)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़) में हुई मुख्य-मुख्य गतिविधियाँ

- **The International Organization of Securities Commissions (IOSCO)**

  - **IOSCO Reviews Implementation of Recommendations for Crypto and Digital Asset Market:** Recognizing rapid development and growth of crypto-asset markets, IOSCO's Financial Stability Board (FSB) published its Final Report regarding Implementation of Recommendations for Crypto and Digital Asset (CDA) Markets for regulation and oversight of crypto-assets and global stable coins. With a focus on investor protection and market integrity, the Review examined how twenty jurisdictions from both advanced and emerging economies, have implemented a set of IOSCO's 2023 Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets. The Review highlights both the progress made in regulating crypto-asset markets and the key areas for continued progress, such as promoting greater consistency in implementation, reducing risks of regulatory arbitrage, and strengthening enforcement practices.

    Press Release: *dated October 16, 2025*

- **Financial Conduct Authority (FCA), The United Kingdom**

  - **FCA supports tokenisation to boost efficiency and innovation in asset management:** The FCA has set out plans to support tokenisation, to drive innovation and growth in asset management. The plans include guidance to provide firms with additional clarity to aid adoption of tokenisation – digital representation of assets on distributed ledger technology.

    Press Release: *dated October 14, 2025*

- **European Securities and Markets Authority (ESMA), Europe**

  - **ESMA proposes key reforms to settlement discipline, supporting the transition to T+1:** The European Securities and Markets Authority (ESMA), has published its final report recommending significant amendments to the Regulatory Technical Standards (RTS) on Settlement Discipline. These changes aim to enhance settlement efficiency across the EU, facilitate the transition to a shorter settlement cycle (T+1) by October 11, 2027 and reduce the administrative burden on central securities depositories and market participants.

    Press Release: *dated October 13, 2025*

- **Financial Stability Board (FSB)**

  - **FSB outlines next steps for authorities on AI monitoring:** FSB published a report highlighting challenges faced by financial authorities, including data gaps and lack of standardised taxonomies, and identifies a range of indicators to support monitoring AI adoption and related vulnerabilities in the financial system. The report also highlights heavy dependence of GenAI on a small number of key suppliers - specialised hardware, cloud infrastructure, and pre-trained models making them vulnerable in absence of alternatives. FSB encourages national authorities to enhance their monitoring approaches, leveraging the indicators presented in the report.

    Press Release *dated Oct 10, 2025*

- **Canadian Securities Administrators (CSA), Canada**

  - **Canadian securities regulators propose semi-annual financial reporting pilot:** CSA has proposed multi-year pilot to allow eligible venture issuers to voluntarily adopt semi-annual financial reporting which exempts them from filing first and third quarter financial reports. It is expected to improve competitiveness of Canadian capital markets by making financial reporting more efficient and cost-effectivey.

    Media Release *dated Oct 23, 2025*

******